

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Demand for waiving of loans taken by weavers

श्रीअलीअनवर अंसारी (बिहार): सर, आन्ध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तक देश के विभिन्न राज्यों में बुनकर खुदकुशी कर रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं, वे कुपोषण का शिकार होकर मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश के करीम नगर जिला के सरसीला में पिछले माह छह बुनकरों ने खुदकुशी कर ली है। अखबारों में खबरें छपी हैं कि पिछले दो साल के अंदर आन्ध्र प्रदेश में 200 बुनकरों ने खुदकुशी की है। उत्तर प्रदेश में बनारस के आसपास बुनकरों के 9 बच्चे कुपोषण के शिकार हो कर अकाल कवलित हो चुके हैं। सर, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार काशी विद्यापीठ प्रखण्ड के धनीपुर गांव में 106 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। डाक्टर ने, जिला प्रशासन ने यह माना है कि इसी प्रखण्ड में 36 पुरुष और 31 महिलाएं टी.बी. से ग्रस्त हैं। यदि उनको अस्पताल से टी.बी. की दवा मिल भी जाती है, तो उनको पोषाहार नहीं मिलता है और इसीलिए वे दोबारा से टीबी के शिकार हो जाते हैं।

महोदय, पिछले सत्र में इसी सदन में हमारे सवाल के जवाब में सरकार ने, माननीय मंत्री वाघेला जी ने कहा था कि बुनकरों पर और जो आर्टिसन क्लास के लोग हैं, उन पर जो बैंकों का कर्ज बकाया है, उसको हम माफ करेंगे, लेकिन वह कर्जा आज तक माफ नहीं किया गया है।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती जयन्ती नटराजन) पीठासीन हुई]

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने भी सदन के बाहर यह कहा था कि किसानों को जिस रेट आफ इंटरैस्ट पर कर्ज मिलता है यानी 7 परसेंट रेट आफ इंटरैस्ट पर बुनकरों को भी कर्ज मिलेगा, लेकिन उनको अभी तक यह कर्ज नहीं मिला है।

महोदय, इस सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और यह संसद क्यों चुप है, इसको देखना है। ये लैंड-लेस लोग हैं और पूरे देश में ये भूख से मर रहे हैं, इस पर संसद क्यों मौन है!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Please conclude now. Your time is over.

श्रीअलीअनवर अंसारी: महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती जयन्ती नटराजन): नहीं, नहीं, आप कनक्लूड कीजिए।

श्रीअलीअनवर अंसारी: महोदय, मैं धूमिल की कविता की दो लाइन सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है?

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार का आश्वासन है, प्रधान मंत्री का आश्वासन है, तो बुनकर, गरीब आदमी इस देश में खुदकुशी क्यों कर रहे हैं, यह संसद क्यों मौन है। सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, सरकार को बुनकरों का कर्ज माफ करना चाहिए, उनके पुष्टतैनी रोजगार धंधे को संरक्षण देना चाहिए, यह हमारी सरकार से मांग है।

श्रीवीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

Serious Flood situation in Tamil Nadu

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Madam. Recently a cyclone called 'Nisha' hit the coast of Tamil Nadu. It caused heavy rains and floods. Eleven districts of Tamil Nadu have been terribly

affected. The rice bowl of Tamil Nadu, which consists of several districts like Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam and Cuddalore, is the worst hit. The loss of property and the loss of standing crop are estimated to the tune of more than Rs.8,000 crore. Over two crore people have been affected. The official figure says that 189 persons were killed due to floods and heavy rain. Farmers, fishermen, and agricultural workers are the people who have been terribly affected by the floods and heavy rain. About 4,997 cattle were killed. Even 1,597 villages are still under water today. The Government figures says that 5,06,675 huts or dwellings were totally destroyed and 4,93,970 huts were partially destroyed.

The State Government has taken some relief measures, but they are not adequate. The central team which visited Tamil Nadu has acknowledged the devastation but yet to make a detailed assessment and proposals. Therefore, I urge upon the Union Government to extend more financial help to the State of Tamil Nadu.

On the basis of the Calamity Relief Fund, the Centre says that it can only give Rs.4,000 per hectare as compensation. The State Government of the day, today, has announced another Rs.3,500. It makes the total amount of Rs.7,500 per hectare. There is a genuine demand from farmers and from many political organisations that the compensation should be from Rs.25,000 to Rs.35,000 per hectare. And this should be given as a relief.

The Government should also think of launching a Comprehensive Crop Insurance Scheme. It is high time the Government came out with concrete proposals for comprehensive crop insurance.

The houses constructed under the Indira Awas Yojana are the worst affected, during these floods and heavy rain. Only Rs.1,000 is given as compensation. It is nothing. Under the Indira Awas Yojana, only Rs.55,000 were given for construction of houses. It is time the Government should think of constructing proper houses under this Scheme. This Scheme is meant for *aam aadmi*, the poor people. The poor people are dalits, agricultural workers, and fishermen in the country. This Scheme should be taken up with more sensitivity.

Finally, Madam, the recommendations of the National Commission on Farmers headed by our distinguished colleague, Prof. M.S. Swaminathan, should be given due consideration. How long can it be kept pending? I do not understand it. We have seen floods in Bihar. We have seen floods in Assam. We have seen floods in Orissa. Now we are seeing floods in Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : Mr. Raja, after three minutes, the mike goes off. ...*(Interruptions)*... We all know that it is an important issue.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand) : Madam, I would like to associate myself with the matter raised by the hon. Member.

The only point I want to make is that it is an unfortunate condition of our country that half of the country is suffering from drought and half of the country is suffering from floods.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTI NATARAJAN) : Ahluwaliaji, you are not allowed to do it.

SHRI S.S. AHLUWALIA: It is a natural calamity. The Natural Calamity Commission should look after this. They should take care of these poor people, and crop insurance should be implemented immediately.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI A. ELAVARASAN (Tamil Nadu): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI N.R. GOVINDARAJAR (Tamil Nadu): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI S. ANBALAGAN (Tamil Nadu): Madam, I associate myself with the mention made by the hon. Member.

Strike by Central University Teachers

डा. मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): महोदया, आज 15 दिसम्बर से सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापक हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि छठे वेतन आयोग के अनुसार उनका वेतनमान भी निर्धारित किया जाना चाहिए और भुगतान किया जाना चाहिए। यह हड़ताल बहुत गहरे परिणाम रखती है, क्योंकि इससे छात्रों तथा उनके अभिभावकों के भविष्य जुड़े हुए हैं। अभी तो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हड़ताल है, फिर यह हड़ताल राज्यों के विश्वविद्यालयों में जाएगी, कॉलेजों में जाएगी। एक अनावश्यक बात पर इस हड़ताल को रोका जा सकता था, वह रोका नहीं गया है। यह काम यूजीसी को दिया जाता है कि वह इनके वेतनमानों का शीघ्र निर्धारण करके निश्चित करे। उन्होंने एक चट्टा कमेटी बनाई। उसकी रिपोर्ट का भी क्या हुआ, सरकार ने क्या दृष्टिकोण लिया, उसमें क्या खामियां हैं, क्या नहीं हैं, इसके बारे में भी न तो सदन को बताया गया है, न देश को बताया गया है। अध्यापकों में घोर असंतोष है। मैं यह चाहूंगा और शायद सदन इस मामले में एक राय होगा कि अध्यापकों की हड़ताल को रोका जाए और उनके वेतनमान ठीक से दुरुस्त करके दिए जाएं। यह बात कि केवल आईएएस अधिकारी अध्यापकों से अधिक तनखाह पाते रहें और अध्यापक की तनखाह उनसे बढ़ न जाए, यह निर्धारण का मानदण्ड नहीं होना चाहिए। अध्यापकों के वेतनमान दुनिया में अनेक स्थानों पर अधिक है।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Madam, Ministers are talking while he is speaking. We can't listen to him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Can we have order please?

डा. मुरली मनोहर जोशी: इस समय शिक्षा मंत्री महोदय बहुत गंभीर वार्तालाप में व्यस्त हैं। इसी से जाहिर होता है कि अध्यापकों के बारे में सरकार की क्या नीति है, क्या दृष्टिकोण है। महोदया, मैं चाहूंगा कि आप कम-से-कम शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करें कि वे सदन में अध्यापकों पर चर्चा की तरफ ध्यान दें, न कि आपस में गंभीर चर्चा पर। मैं जानता हूं कि जाबिर हुसैन साहब बहुत बड़े साहित्यकार हैं और मंत्री महोदय उन्हीं के राज्य से आते हैं, लेकिन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापक आपकी जिम्मेदारी हैं, जो आज हड़ताल पर गए हैं। मैं जानना